भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *257

20 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

इस्पात का उत्पादन

***257. श्री थॉमस चाज़िकाडन**:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में इस्पात के उत्पादन में कितना बदलाव दर्ज किया गया है और इसके उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस्पात के निर्यात में गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की तीन इकाइयों अर्थात् कर्नाटक में भद्रावती स्थित विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआईएसपी), तमिलनाडु में सेलम स्टील प्लांट (एसएसपी) और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्थित एलॉय स्टील्स प्लांट (एएसपी) के कार्यनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)**

(क) से (ड.): एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

'इस्पात के उत्पादन' के संबंध में संसद सदस्य श्री थॉमस चाज़िकाडन द्वारा दिनांक 20 दिसंबर, 2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *257 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): विगत पांच वर्षों के दौरान क्रूड इस्पात के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है और इससे 5 वर्ष की अवधि के दौरान 4.3% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) का संकेत मिलता है।

वर्ष	क्रूड इस्पात उत्पादन मात्रा (एमटी)
2018-19	110.92
2019-20	109.14
2020-21	103.54
2021-22	120.29
2022-23	127.20
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); एमटी=मिलियन टन	

(ख): विगत पाँच वर्षों में कुल तैयार इस्पात के समग्र निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है और इससे वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 के दौरान वृद्धि का संकेत मिलता है जबकि वर्ष 2022-23 के दौरान घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए कतिपय इस्पात उत्पादों पर निर्यात शुल्क लागू किए जाने के कारण निर्यात में कमी आयी।

तैयार इस्पात का निर्यात		
वर्ष	मात्रा (एमटी)	विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में % परिवर्तन
2018-19	6.36	-
2019-20	8.36	31.4
2020-21	10.78	29.1
2021-22	13.49	25.1
2022-23	6.72	-50.2
स्रोत: जेपीसी;		

(ग): सरकार ने इस्पात क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को आकर्षित करके देश में विशेष इस्पात ग्रेड के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए 'विशेष इस्पात' हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अनुमोदन प्रदान किया है। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत आने वाली विभिन्न इस्पात श्रेणियों के लिए 57 आवेदनों को शामिल करते हुए 27 कंपनियों के साथ दिनांक 17.03.2023 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा, सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया है जिससे अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा मिलता है। इससे इस्पात की मांग में वृद्धि होने की आशा है। अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के साथ यह उपाय भी किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप, इस्पात एवं अन्य निर्माण सामग्रियों की मांग बढ़ेगी।

(घ) और (ड.): सेल के 3 संयंत्रों अर्थात् विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात संयंत्र (वीआईएसपी), सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी) तथा अलॉय इस्पात संयंत्र (एएसपी) का रणनीतिक विनिवेश निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा कराया जाना है। फिलहाल, विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात संयंत्र के लिए रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रक्रिया को पर्याप्त बोलीदाताओं में आगे बढ़ने की रूचि की कमी के कारण रद्द कर दिया गया है और अलॉय इस्पात संयंत्र के लिए कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया है।

*****